

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी,  
जैतारण (जिला-पाली) राज.

मुख्य अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 116/2021  
GCMS NO. : 2021/207

-: प्रार्थीगण :-

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

- |  |   |
|--|---|
| 1. रामस्वरूप पुत्र घेवरराम   | 1. बाबूलाल पुत्र हरकाराम  |
| 2. हापूराम पुत्र घेवरराम जाति जाट<br>निवासी डिगरना तहसील जैतारण<br>जिला पाली राज०। | 2. जीयाराम पुत्र हरकाराम<br>3. पिरता पुत्री हरकाराम<br>4. ढगलाई पत्नी हरकाराम जाति<br>जाट निवासीगण डिगरना तहसील-<br>जैतारण जिला पाली। |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी

प्रकरण संख्या 196/2018 बअनवान बाबूलाल व अन्य बनाम रामस्वरूप व अन्य में  
पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 11.06.2019 को सेटेसाइड करने बाबत।

तारीख रजु: 16/07/2021

- उपस्थित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।  
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

-: निर्णय :-

दिनांक:- 30/08/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी, के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण बाबूलाल वगैरा ने प्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वादपत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 5-14 बीघा की आई हुई है जिसके अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है, जमाबन्दी में उनका नाम है मौके पर कब्जा काश्त है खेत के चारो तरफ खन्दक लगी हुई है और दिनांक 10/07/2018 को खेत में तिल की फसल बो रहे थे इतने में प्रार्थीगण मौके पर आये और उन्होंने दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया और कहा कि यह कृषि भूमि हमारी है और उनके हक अधिकारो पर कुठाराघात करने लगे तब अप्रार्थीगण ने एक वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रार्थीगण को मिलने के पश्चात दिनांक 24/09/2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बावजूद तामिल के अनुपस्थित मानकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 11/06/2019 को प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का अप्रार्थीगण वादी के विरुद्ध यह प्रार्थनापत्र बाबत एकपक्षीय डिक्री को सेटेसाइड करने का निम्नलिखित आधारो पर श्रीमान् के समक्ष पेश है- 1 प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण बुर्जुग व्यक्ति है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 को सम्मन दिये थे लेकिन प्रार्थी संख्या 1 बुर्जुग व्यक्ति है। और उस समय वो बीमार रहते थे इस कारण से उक्त सम्मन नोटिस बाबत अपने परिवार के किसी सदस्य को सूचना नहीं दे पाये और न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई। 2 प्रार्थी संख्या 2 जो कि उस दिन गांव में ही थे लेकिन अप्रार्थीगण वादी ने जमानबुझकर तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत करके उनको सम्मन नहीं दिया और दोनो ही

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक क्लर्क,  
जैतारण, जिला-पाली

सम्मान तामिल प्रार्थी संख्या 1 से करवाये गये थे और प्रार्थी संख्या 1 बुजुग व्यक्ति है था उस समय बिमार थे उनको कम दिखाई देता था उनको सम्मान नोटिस में क्या रखा है इस बाबत कोई जानकारी नहीं होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, इस कारण न्यायालय ने प्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई तामिल को सभी प्रतिवादीगण की तामिल मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो काबिल सेटेसाइड के है। 3 वादग्रस्त सम्पति का प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने खरीद कर रखी थी और पिछले करीबन 50 वर्षों से प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का ही मौके पर कब्जा काशत है, वादग्रस्त सम्पति अप्रार्थीगण के पति व पति ने दिनांक 13/09/1985 को 7 रुपये के स्टाम्प पर एक लिखित बेचाननामा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में तकमील किया तब से लेकर के आज दिन तक प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का कब्जा है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम इन्द्राज है और इसी आधार पर अब अप्रार्थीगण की नियत में खोटा आ गई और वह बेचान की गई सम्पति को राजस्व रेकॉर्ड में नाम रह जाने मात्र से पुनः हडप करना चाहते हैं। इसलिए उन्होने न्यायालय हाजा में वादपत्र पेश कर एकपक्षीय डिकी पारित करवाई जबकि अप्रार्थीगण वादी द्वारा प्रार्थीगण के काशत करते समय दखलन्दाजी की तब प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने अप्रार्थीगण वादी को बेचान की गई भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण वादी इन्कार हो गये तब प्रार्थीगण प्रतिवादी ने 1985 में खरीद की गई सम्पति बाबत दिनांक 05/07/2019 को सिविल न्यायालय में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का वादपत्र पेश किया जो वर्तमान समय में सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और अप्रार्थीगण वादी के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी हो रखा है इन सब तथ्यों की अप्रार्थीगण वादी को जानकारी होते हुए भी उन्होने बाले बाले एकपक्षीय डिकी पारित करवा ली और सिविल न्यायालय में चल रहे वादपत्र का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए जब तक हक अधिकार सिविल न्यायालय तय नहीं कर सकता है तब तक इस डिकी की आड में अप्रार्थीगण वादीगण प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की भूमि में हस्तक्षेप करेगे तो प्रार्थीगण के हितों के विरुद्ध भारी कुठाराघात होगा इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित की गई एकपक्षीय डिकी को सेटेसाइड किया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में जबाब पेश करने एवं अपने साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करावे जिससे कि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके क्योंकि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वादपत्र विचाराधीन है और दोनों पक्षों के हक अधिकार सिविल न्यायालय में तय होंगे इसलिए दिनांक 11/06/2019 को पारित की गई एकपक्षीय डिकी को सेटेसाइड कर प्रकरण को पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर प्रार्थीगण को अपना जबाब एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिलावे। अन्य उजर बरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06/07/2021 को उक्त डिकी की प्रति प्रार्थीगण को बताकर उक्त सम्पति में दखलन्दाजी करने की कोशिश की तब प्रार्थीगण को उक्त एकपक्षीय पारित डिकी की जानकारी होने से यह अन्दर मियाद प्रार्थनापत्र बाबत सेटेसाइड डिकी का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थनापत्र पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मान तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना

उपस्थित अधिकारी एवं  
पदेन सहायक क्लर्क,  
जैतपुरा जिला-पाली

प्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथन का जवाब है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद संख्या 196/18 अनवान लाल वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा के विरुद्ध धारा 188 आर.टी. एक्ट का पेश करने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सम्मन की प्रति पर व्यक्तिगत रूप से तामिली रिपोर्ट देने पर व दिनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिए गए तत्पश्चात वादी की साक्ष्य होने के उपरान्त बाद इस दिनांक 11.06.2019 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की, जो विधिनुरूप व साथ संगत है तथा प्रार्थीगण ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने के जो आधार अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित किये जो समुचित व प्रयाप्त तथा संतोषजनक नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जवाब है कि प्रार्थी संख्या 1 पढा दिखा, सेवानिवृत्त फौजी हैं तथा वर्तमान में ग्राम डिगरना के बाजार में किराणा की दुकान व व्यवसाय करता है। जिसने न्यायालय द्वारा आये सम्मन पर व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामिल कर प्राप्त किया व अपने हस्ताक्षर किए व प्रकरण के सभी तथ्यों की जानकारी थी तो फिर प्रार्थीगण द्वारा यह कथन करना कि बुजुर्ग होकर बीमार रहने व परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं करना आदि के कथन गलत झूठे व मनमाने अंकित किये हैं। न्यायालय के सम्मन की सम्यक रूप से तामिल होने पर ही न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए, जो सही हैं तथा प्रार्थी ने बीमार होने के कथन किए, परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर का कोई प्रमाण - पत्र व पर्ची आदि भी नहीं हैं। प्रार्थीगण पुर्णतया स्वस्थ होकर अपना काम करते हैं। 2 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में गलत झूठे अंकित किये हैं जिसे अप्रार्थीगण/वादीगण नामन्जूर करते हैं तथा अप्रार्थीगण /तामिल वादीगण वक्त तामिल न तो उपस्थित थे व न ही कुनिन्दा से कोई मिलीभगती की। जबकि प्रार्थी संख्या 1 स्व- शिक्षित सेवानिवृत्त फौजी था जिसने स्वयं ने अपने सगे भाई का सम्मन/नोटिस प्राप्त कर सूचना करने का कहकर प्राप्त किए तो फिर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने को बुजुर्ग होकर बीमार होना, कम दिखाई देना, सम्मन के बारे में जानकारी नहीं होना व न्यायालय में इस कारण से उपस्थित नहीं होने आदि के कथन प्रार्थना पत्र करने की गज से गलत व झूठे अंकित किये हैं जबकि श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत वाद के बाद प्रार्थीगण ने श्रीमान सिविल जज साहब जैतारण के यहां 05 जुलाई 2019 को एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व एक वाद संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थीगण सजग रहकर पैरवी कर रहे हैं तो इस प्रकरण के सम्मन/नोटिस की तामिल प्रोपर नहीं होने के कथन कतई मानने योग्य नहीं हैं जबकि सम्मन/नोटिस की तामिल प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से होने पर व अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए व तत्पश्चात दिनांक 11.06.2019 को वाद डिक्री हुआ, जो न्यायसंगत है। 3. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 के कथनों का जवाब है कि इस पद में अंकित कथनों का प्रार्थना पत्र से कोई रिलीवेन्सी नहीं है। जबकि बाद में वर्णित खसरा नम्बर 761 रकबा 05-14 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने व अप्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा दिनांक 13.09.1985 को 7/ रुपये स्टाम्प पर एक लिखित वैचान इकरार प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करने से लेकर आज दिन तक कब्जा होने के कथन भी गलत हैं। जबकि कब्जे बाबत कोई गिरदावरी या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए जबकि तथाकथित लिखित का स्टाम्प प्रति प्रार्थी/वादी रामस्वरूप

उपखण्ड अधिवक्ता एवं

पदेन सहायक कलेक्टर,

दिल्ली

अपने लाभ के लिए लिया, जो फर्जी कुट रचित दस्तावेज हैं। उक्त भूमि बाबत प्रार्थीगण के पिता ने कोई सौदा नहीं किया व ना हुआ न ही तथाकथित लिखित बचान करार निर्धारित मुद्रांको पर निष्पादित नहीं होने से कानूनन प्रवर्तनीय नहीं है। उक्त दस्तावेज मियाद बाहर हैं तथा न ही उक्त भूमि के खातेदार हो सकते हैं जबकि प्रार्थीगण/वादीगण ही उक्त भूमि के खातेदार व स्वामित्व की हैं। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी/प्रतिवादी रामस्वरूप ने दिनांक 05.07.2019 को एक सिविल वाद संघिदा की विनिर्दिष्ट पालना का विरुद्ध अपार्थीगण/वादी के पेश किया जिसमें दिनांक 20.09.201 को अपार्थीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके पद संख्या 5 में यह कबन किए कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद डिक्री दिनांक 11.06.2019 को विरुद्ध प्रार्थीगण के हुआ। जिससे भी प्रार्थीगण को राजस्व वाद की जानकारी हो गई थी। जिसके बाद प्रार्थीगण ने सम्यक रूप से होने पर व अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए व तत्पश्चात दिनांक 11.06.2019 को वाद डिक्री हुआ, जो न्यायसंगत है। यह प्रार्थना पत्र एकपक्षीय डिक्री अपारत करने का 2 वर्ष 1 माह बाद बहुत ही देरीना प्रस्तुत किया, जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी को सम्मनोटिस की तामील सम्यक रूप से हो गई थी इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपारत करने के अपने प्रार्थना पत्र में पर्याप्त हेतुक/समुचित/संतोषजनक आधार अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है. व न ही म्याद को माफ करने बाबत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया तथा कानूनन डिक्री को अपारत करने की जानकारी दिनांक 20.09.2019 को होने के 30 दिन के भीतर आर्टिकल 123 के तहत भी प्रार्थना पत्र अन्दरम्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस तामीली में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई हैं। पूर्ववर्ती राजस्व वाद में पश्चातवर्ती सिविल वाद का अस्तित्व नहीं होने से कोई जिक्र नहीं किया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ - पत्र व दस्तावेज पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं हैं। मय खर्चा खारिज फरमावें।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थीगण द्वारा अपार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 196/2018 बअनवान बाबूलाल वगैराह बनाम रामस्वरूप वगैराह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2019 को अपारत किया जावे। अपार्थीगण ने एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा दिनांक 24.09.2018 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बावजूद तामील के अनुपस्थित मानकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा प्रकरण में सम्मन प्रार्थी संख्या एक को दे दिये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा लम्बे समय से बीमार रहते थे इस कारण से उक्त सम्मन नोटिस परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दे पाये और न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो पाये। प्रकरण में प्रार्थी संख्या दो गांव में

उपरोक्त/अधिवक्ता एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जिला न्यायालय

स्थित होने के बावजूद वादी ने जानबूझकर तामिल कुनिदा से मिलीभगत कर सम्मन मिल प्रार्थी संख्या एक से करवाई गई, जिसकी सूचना प्रार्थी संख्या दो को नहीं हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन पर हुई तामिल सम्यक तामिल नहीं मानी जा सकती। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.07.2021 को उक्त डिक्री की प्रति प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को भेजा कर उक्त सम्पत्ति में दखलावाजी करने की कोशिश की तब प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त एकपक्षीय डिक्री की जानकारी होने से प्रार्थनापत्र अन्दर वाद पेश किया गया। अतः दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री अपास्त कर प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को वाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करावै।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते ये कथन किया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन की प्रति पर व्यक्तिगत रूप से तामिली रिपोर्ट आने पर व दिनांक 24.09.2018 को अनुपस्थित रहने पर न्यायालय पक्षा द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् वादी साक्ष्य एवं गवाह उपरांत दिनांक 11.06.2019 को एकपक्षीय डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतः विधि अनुरूप एवं न्याय संगत है। प्रार्थी संख्या एक पक्ष लिखा सेवानिवृत्त कौजी है तथा ग्राम डिगरना के बाजार में किराणा की दुकान व व्यवसाय करता है। तामिल कुनिदा द्वारा पूर्णतया सही एवं उचित तामिल करवाई गई है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विलम्बकाल को माफ करने बाबत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद नहीं होने से पोषणीय नहीं है।

3. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत एक पक्षीय डिक्री की जानकारी दिनांक 06.07.2021 को होना अंकित किया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य को किसी विश्वसनीय आधार पर खण्डित नहीं किया गया। लिहाजा यह माना जाना चाहिए कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत डिक्री की जानकारी 06.07.2021 को ही हुई है। तथा प्रार्थीगण द्वारा 15.07.2021 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जो कानूनन अन्दर म्याद है।

4. आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विधिक प्रावधान निम्नानुसार है-  
 “प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना- किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामिल सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।”


5. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वादपत्र के सम्मन की प्रमाणित प्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी हापुराम वल्द घेवरराम के नाम जारी सम्मन रामस्वरूप द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से तामिल किया जाना अंकित है। इसी प्रकार रामस्वरूप वल्द घेवरराम के

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक क्लर्क,  
 न्यायालय, दिल्ली-एनएच


म जारी सम्मन स्वयं रामस्वरूप द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से तामिल किया जाना अंकित। चूंकि प्रार्थीगण रामस्वरूप एवं हापुराम परस्पर भाई है तथा अप्रार्थीगण के जवाब के अनुसार रामस्वरूप सेना से सेवानिवृत्त है, इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों भाई बालिग है। प्रार्थीगण द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि रामस्वरूप एवं हापुराम एक ही रिवाज के सदस्य है। इसलिए यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रार्थीगण प्रस्क है तथा दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है लिहाजा प्रकरण में तामिल उपर्युक्त दोनों क्षकारान् की व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। अतः उक्त तामिल को सम्यक रूप से निष्पादित तामिल की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। तथा समुचित तामिल के अभाव में प्रार्थी हापुराम पुत्र घेवरराम के विरुद्ध दिनांक 24.09.2018 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त योग्य है। जिसके फलस्वरूप वादपत्र संख्या 196/2018 बाबूलाल वगैरह बनाम रामस्वरूप वगैरह में दिनांक 11.06.2019 को पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना विधिसंगत होगा।

**-:: आदेश ::-**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखुबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के राजस्व वादपत्र संख्या 196/2018 में प्रतिवादी संख्या 2 हापुराम पुत्र घेवरराम के विरुद्ध दिनांक 24.09.2018 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2019 को अपास्त किया जाता है। राजस्व वादपत्र संख्या 196/2018 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली प्रतिवादी जवाबदावा में नियत कि जावे। प्रार्थनापत्र इसी मुताबिक निर्णित होकर बादतकमील संख्या से एक कम हो।

  
राजवाह अशिक्षी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जैतारण, (जिला-पाली)

